राजीव नारायण रैना, नयायाधिपती के सामने।

ईएएसआई राजपाल-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य-प्रतिवादी

2013 का सी.डबलिउ.पी. नंबर 21001

सितम्बर 20,2013

भारत का संविधान, 1950 - कला, 226 - भारतीय दंड संहिता, I860 - सीमा अधिनियम, 1963 - पंजाब पुलिस नियम, 1934 - सेवा कानून - विभागीय जांच - आपराधिक मामला - बरी - याचिकाकर्ता एक छूट प्राप्त सहायक पुलिस उप-निरीक्षक हवाई पट्टी का प्रभारी था कुअर्ड - हिंट में काम करने वाले एक कांस्टेबल ने अपने खिलाफ आईपीसी की धारा 323,377 और 511 के तहत एफआईआर दर्ज कराई - याचिकाकर्ता को आपराधिक मुकदमे का सामना करना पड़ा - विभाग ने उसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू की - जांच अधिकारी ने उसे दोषी पाया - याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया - अपीलीय प्राधिकारी ने अपील खारिज कर दी - संशोधन को प्राथमिकता दी गई याचिकाकर्ता को पुलिस महानिदेशक ने खारिज कर दिया - याचिकाकर्ता को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने यह कहकर बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष के साक्ष्य दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं थे - बरी होने के बाद।

याचिकाकर्ता ने एक अभ्यावेदन दिया - अभ्यावेदन पर अधिकारियों द्वारा निर्णय नहीं लिया गया - सिविल रिट याचिका दायर की गई – निर्धारित किया गया, विभागीय कार्यवाही और एक आपराधिक मुकदमे में आरोप लाने के लिए आवश्यक सबूत के मानक के बीच अंतर है - आगे कहा गया। कार्रवाई का कारण 28.08.2008 को उत्पन्न हुआ - सिविल सूट 20H में कालातीत हो गया होगा - रिट तब तक झूठ नहीं होगी जब तक कि अदालत को गंभीर उल्लंघन या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं मिलता - बरी करने का निर्णय किसी प्रशासनिक के खिलाफ कार्रवाई का नया कारण पैदा नहीं करेगा आदेश - सबसे गंभीर प्रकार का कदाचार – स्तर के प्रश्न का सबसे अच्छा निर्णय वे लोग कर सकते हैं जो पुलिस बल चलाते हैं - सिविल रिट याचिका खारिज कर दी गई।

निर्धारित किया गया कि विचार के लिए जो संक्षिप्त प्रश्न उठता है वह यह है कि क्या विभागीय कार्यवाही से उत्पन्न पुलिस महानिदेशक, हरियाणा द्वारा संशोधन तक पुष्टि किए गए बर्खास्तगी आदेश को बाद में बरी किए जाने के कारण वापस लिया जा सकता है, बदला जा सकता है, संशोधित किया जा सकता है या रद्द किया जा सकता है।

(पैरा 8)

आगे निर्णय लिया गया कि, लेकिन इस तर्क में, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील विभागीय कार्यवाही और आपराधिक मुकदमे में आरोप लाने के लिए आवश्यक सबूत के मानक के बीच अच्छी तरह से स्थापित अंतर को भूल जाते हैं। यह दोहराना सामान्य बात है कि एक संभावनाओं की प्रबलता पर आधारित है जबकि दूसरा किसी भी उचित संदेह की छाया से परे प्रमाण पर आधारित है। आपराधिक कानून में संदेह का लाभ देकर आपराधिक आरोप से बरी करना बाकी दुनिया के लिए निर्दोषता के बराबर है, लेकिन सेवा न्यायशास्त्र में सेवा में बनाए रखने के लिए सिद्धांत को आंख मूंदकर स्वीकार नहीं किया जा सकता है या उसका पालन नहीं किया जा सकता है। एक वर्दीधारी बल में सेवा के लिए आवश्यक उच्च नैतिक और नैतिक मानकों से निपटने और पुलिस बलों में केवल बेदाग सर्वश्रेष्ठ को प्रवेश देने में शुद्धता और पूर्ण सत्यता बनाए रखने के साथ-साथ अब यह वर्तमान आवश्यकता है कि आवेदन पत्रों में दिए गए बयानों में सच्चे और ईमानदार खुलासे हों। FI IVs के पंजीकरण का पिछला आपराधिक रिकॉर्ड और उसके बाद जांच और परीक्षण के चरण और विज्ञापित सरकारी पदों पर नियुक्तियों की मांग करते समय मांगे गए उनके इकबालिया आवेदन और गैर-नियुक्ति को उचित ठहराने वाले भौतिक तथ्यों के गैर-प्रकटीकरण के प्रभाव के संबंध में, यह मुद्दा उचित है। सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के उच्चतम नैतिक मानकों की मांग करने वाले सार्वजनिक हित के खिलाफ संदिग्ध लोगों को सार्वजनिक कार्यालय में प्रवेश देने की प्रवृत्ति से उत्पन्न होने वाले बड़े सामाजिक मुद्दों की जांच की जानी चाहिए, खासकर उन लोगों से जो वेतन पर काम करते हैं। नागरिकों के सेवा जीवन के हर दिन जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सार्वजनिक धन। यह दो अल्पविरामों के बीच लगाने के लिए एक बड़ा वाक्य हो सकता है, लेकिन आधुनिक शासन का व्याकरण- शुद्धिकरण अब शुरू होना चाहिए क्योंकि इससे पहले कभी भी कार्यालयधारकों में विश्वास की पूर्ण हानि नहीं हुई है और विश्वास की हानि के कारण और अधिक नुकसान हुआ है जो आमतौर पर दागी भर्ती प्रक्रियाओं के साथ चलता है। उन प्रतिष्ठित व्यक्तियों की मूल सोच को बहाल किया जाना चाहिए जिन्होंने संविधान सभा के थिंक टैंक का गठन किया, जिसने हमें हमारा संविधान और लोक सेवा आयोग दिए, जिन्हें अपनी संवैधानिक स्थिति

को बचाने की जरूरत है। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि न्यायालय विश्वास, विश्वास और आपसी सम्मान को बढ़ावा देने के लिए अनुस्मारक कहे, जब शासन अदूरदर्शी, निचले स्तर पर और कंचनजंगा से भी अधिक भ्रष्टाचार वाला प्रतीत होता है। यह सत्तारूढ़ सिद्धांत पुलिस विभाग में बहुत आवश्यक सुधार है, जिसे लोगों की आकांक्षाओं और आशाओं के अनुरूप शुरू किया जाना चाहिए। इसका हम पर और हमारी सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ता है और जो लोग हमारे हवाई अड्डों और हमारे जीवन की रक्षा करते हैं, उन्हें सीज़र की पत्नी की तरह संदेह से परे होना चाहिए।

(पैरा 11)

आगे निर्णय लिया गया कि विषयांतर के बावजूद, 20.08.2008 को पुलिस महानिदेशक, हरियाणा द्वारा पुनरीक्षण याचिका को खारिज करने के साथ याचिकाकर्ता के पक्ष में कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ। यदि 20.08.2008 को पुनरीक्षण याचिका की अस्वीकृति के चरण तक बर्खास्तगी के आक्षेपित आदेशों पर सवाल उठाने के लिए एक सिविल मुकदमा लाया गया था, तो इसे 20.08.2011 को या अधिकतम 20.10.2008 को दो लोगों को भत्ता देते हुए समय बाधित किया गया होगा। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 80 के तहत महीनों का नोटिस। यदि किसी मुकदमे को कार्रवाई के कारण वर्जित किया जाएगा तो आम तौर पर एक रिट तब तक झूठ नहीं होगी जब तक कि यह न्यायालय अपने असाधारण रिट क्षेत्राधिकार में मौलिक अधिकारों या मानव अधिकारों का गंभीर उल्लंघन या उल्लंघन नहीं पाता है। सही उल्लंघन शामिल है जिसके लिए तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है। तब शायद यह न्यायालय सीमा अधिनियम, 1963 या विशेष वैधानिक कानून द्वारा निर्धारित ऐसी अन्य बाधाओं के तहत कार्रवाई करने के लिए निर्धारित अवधि से बाहर होने के परिणामस्वरूप होने वाली देरी, विलंब और बाधा के सिद्धांतों पर उचित दावे को खारिज करने पर जोर नहीं दे सकता है।

(पैरा 12)

आगे निर्णय लिया गया कि वर्तमान में विचार करने योग्य बात यह है कि क्या दोषमुक्ति के फैसले को कार्रवाई के अधिकार या कार्रवाई के कारण को जन्म देने वाला कहा जा सकता है। मुझे नहीं लगता कि इस न्यायालय के लिए यह मानना सही होगा कि किसी घटना के आधार पर आपराधिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा बरी करने का निर्णय जो पहले विभागीय कार्यवाही में हुआ हो और जुर्माना लगाया गया हो, उसके खिलाफ कार्रवाई का एक नया कारण उत्पन्न होगा

एक प्रतिकूल प्रशासनिक आदेश अंतिम रूप ले चुका है या कानून की अदालत में दंड के खिलाफ लागू किया जा सकता है, उदाहरण के लिए, सेवा से बर्खास्तगी, सबूत के मानक दोनों के अलग होने के बावजूद।

(पैरा 13)

इसके अलावा, यह आग्रह किया गया कि याचिकाकर्ता ने घटना से पहले 32 साल से अधिक समय तक सेवा की थी, 1975 में कांस्टेबल के रूप में उसकी भर्ती का वर्ष दिया गया था और उसे बर्खास्तगी की कठोरतम सजा न देने का पर्याप्त औचित्य होना चाहिए, जो तर्क करता है मीडिया को प्रभावित न करें या हिरासत में न लें दिनांक 29.11.2007 के आदेश में अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने विशेष रूप से माना था कि डिफॉल्टर का कदाचार निश्चित रूप से सबसे गंभीर प्रकार का है और उसकी सेवा की अवधि आदि को देखते हुए उसके साथ व्यवहार करने में कोई उदारता नहीं दिखाई जा सकती है। पुलिस बल के हित के विरुद्ध एक भावनात्मक निर्णय होगा। कदाचार के गंभीरतम कृत्यों से जुड़े पीपीआर, 1934 के तहत मामलों से निपटने के दौरान यह पूरी तरह से अच्छा और स्वीकार्य कारण है। क्या गंभीर और गंभीर है यह डिग्रियों का प्रश्न है जिसमें कई परिवर्तनशील कारक शामिल होते हैं जिनका सबसे अच्छा निर्णय वे लोग करते हैं जिन्हें पुलिस बल चलाना है। याचिकाकर्ता के पास न तो योग्यता के आधार पर, न ही समानता के आधार पर और न ही किसी सहानुभूतिपूर्ण विचार के आधार पर मामला है। दिए गए तथ्य स्थितियों के एक सेट के खिलाफ परीक्षण की गई सहानुभूति और करुणा पूरी तरह से व्यक्तिपरक राय हैं जो आमतौर पर न्यायिक रूप से प्रबंधनीय मानकों से परे होती हैं और इससे भी बुरी बात यह है कि वे सरकारी कार्यालय और अदालत से अदालत में निर्णय-निर्माता सह-कर्तव्य-धारक से भिन्न हो सकते हैं।

(पैरा 14)

इसके अलावा, निर्धारित किया जाता है कि बर्खास्तगी के आदेशों के खिलाफ हस्तक्षेप की कोई उचित आवश्यकता नहीं है, जो बहुत पहले ही अंतिम रूप ले चुके हैं। उन्हें कानूनी और वैध माना जाता है और वे किसी भी कमजोरी से ग्रस्त नहीं हैं।

(पैरा 17)

याचिकाकर्ता के वकील, मनोज ताया

राजटीवी नारायण रैना, नयायाधिपती।

(1) याचिकाकर्ता के खिलाफ एफआईआर संख्या 93 दिनांक 22.05.2007 धारा 323,377, 511 आई पीसी के तहत पुलिस स्टेशन कुंजपुरा में दर्ज की गई थी। द. याचिकाकर्ता एक एक्सेम्प्टी सहायक पुलिस उपनिरीक्षक था और हवाईपट्टी में प्रभारी हवाई पट्टी गार्ड, कलवेहरी के रूप में तैनात था। कॉन्स्टेबल ("सीटी.") अशोक कुमार एयरबेस पर उनके अधीन कार्यरत थे। सी.टी. अशोक कुमार ने याचिकाकर्ता के खिलाफ एक आपराधिक शिकायत की जिसके कारण उपरोक्त एचआर का पंजीकरण हुआ। कांस्टेबल ने कहा कि 21.05.2007 को जब वह याचिकाकर्ता के साथ एयरबेस पर गार्ड प्रभारी के रूप में प्रतिनियुक्त था, तो याचिकाकर्ता ने शाम के समय शराब पीने के बाद अक्सर उसे शराब पिलाई, जिसे उसने देने से इनकार कर दिया। कांस्टेबल ने शिकायत की कि रात करीब साढ़े दस बजे याचिकाकर्ता ने उसके साथ जबरदस्ती की और उसकी पतलून और अंडरवियर उतार दिया और उसके साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का प्रयास किया (शिकायत में हस्तमैथुन के रूप में दर्शाया गया है)। जब शिकायतकर्ता ने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई और अंगूठे पर काट लिया, लेकिन इसके बाद हमलावर मौके से भाग गया। इस प्रकार आपराधिक कानून को क्रियान्वित किया गया।

(2) याचिकाकर्ता को उपरोक्त अपराधों के लिए आपराधिक मुकदमे का सामना करना पड़ा। प्रतिवादी-विभाग ने घटना का संज्ञान लिया और याचिकाकर्ता के खिलाफ तुरंत उपरोक्त आरोपों पर आरोप-पत्र देकर और एक साथी पुलिसकर्मी के साथ दुर्व्यवहार की नियमित जांच का आदेश देकर विभागीय कार्यवाही शुरू की। उसी घटना पर 29.06.2007 को आरोप पत्र जारी किया गया था जो आपराधिक मुकदमे का विषय था। कहा गया है कि कदाचार करते हुए याचिकाकर्ता ने घोर लापरवाही और अनुशासनहीनता प्रदर्शित की है जिससे विभाग की बदनामी होगी। 'पुलिस उपाधीक्षक, असंध को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था। याचिकाकर्ता जांच से जुड़ा था। अभियोजन और बचाव पक्ष के साक्ष्य पेश किए गए और उन्हें अपने खिलाफ पेश किए गए गवाहों से जिरह करने का पूरा मौका मिला। जांच के समापन पर, रिपोर्ट 24.09.2007 को प्रस्तुत की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कमल ने लगाए गए आरोपों के संबंध में जांच अधिकारी द्वारा निकाले गए निष्कर्ष से असंतुष्ट होकर आरोप सिद्ध पाया। तदनुसार 31.10.2007 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। जवाब मिला। इस पर विचार किया गया और याचिकाकर्ता को सेवा से

बर्खास्त करते हुए दिनांक 29.11.2007 (पी-6) का आक्षेपित आदेश पारित किया गया। याचिकाकर्ता को 22.05.2007 को उसकी गिरफ्तारी के बाद निलंबित कर दिया गया था और निलंबन के दौरान बर्खास्त कर दिया गया था। पुलिस महानिरीक्षक, रोहतक रेंज, रोहतक के समक्ष उनकी अपील 20.12.2007 को खारिज कर दी गई क्योंकि अपील में कोई योग्यता नहीं पाई गई थी। याचिकाकर्ता को अपीलीय प्राधिकारी द्वारा 18.03.2008 को व्यक्तिगत रूप से सुना गया, जिन्हें बर्खास्तगी के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिला।

(3) अपील में निर्णय से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने पुलिस महानिदेशक, हरियाणा से संपर्क कर सभी परिणामी लाभों के साथ बहाली की प्रार्थना की और दावा किया कि उसके साथ गलत हुआ है। बचाव पक्ष यह था कि शिकायतकर्ता कांस्टेबल अशोक कुमार की आदत थी अप्राकृतिक यौनाचार करना और अप्राकृतिक यौनाचार किया जाना। सीधा तात्पर्य यह था कि कांस्टेबल समलैंगिक था। याचिकाकर्ता ने बचाव पक्ष के गवाह ईआई आईसी होशियार सिंह, प्रभारी गार्ड, हवाई अड्डा, कलवचरी को भी पेश किया, जिन्होंने कहा कि रात में जब वह और कांस्टेबल अशोक कुमार गार्ड ड्यूटी पर अकेले थे, तो शिकायतकर्ता ने उनसे अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। ऐसा करने के लिए। बचाव पक्ष के एक अन्य गवाह ईएचसी चंद्रकर सिंह यह कहते हुए गवाह बने कि उन्होंने एक बार शिकायतकर्ता को एक रिक्शा चालक के साथ अप्राकृतिक यौनाचार करते हुए देखा था। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि इन तथ्यों की सराहना नहीं की गई या उन पर विचार नहीं किया गया और शिकायतकर्ता कांस्टेबल अशोक कुमार द्वारा रची गई कहानी झूठी थी और अपीलकर्ता के खिलाफ अप्राकृतिक यौनाचार की मनगढ़ंत कहानी थी और इसलिए उन्होंने याचिकाकर्ता के खिलाफ पुलिस के एएसआई राम सिंह से शिकायत की। थाना कुंजपुरा जब वह गश्त ड्यूटी पर थे।

(4) याचिकाकर्ता ने गवाहों के बयान में विसंगतियों के आधार पर मुद्दे उठाए हैं कि कथित अपराध के स्थान पर कांस्टेबल अशोक कुमार के कपड़े उतारने की स्थिति क्या थी, क्या वह केवल अंडरवियर में सो रहा था या क्या वह वर्दी में सो रहा था, ' याचिकाकर्ता ने इस तरह का अजीब और शुद्ध बचाव किया; शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि याचिकाकर्ता ने शराब का सेवन किया था, लेकिन उसके ब्रांड नाम का खुलासा नहीं किया था या यह नहीं बताया था कि वह 'अंग्रेजी' थी या 'देशी बनी'; शिकायतकर्ता कथित घटना

के समय पी गई शराब की मात्रा का खुलासा करने में भी विफल रहा। यह याचिकाकर्ता के कपटी दिमाग को दर्शाता है।' वकील ने कहा कि शराब का सेवन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, कुंजपुरा द्वारा जारी एमएलआर द्वारा समर्थित नहीं है। अपील में याचिकाकर्ता ने अपने अनुसार मामले के पीछे का मुख्य कारण इस प्रकार बताया है:-

"(ix) सोडोमी के इस गैरकानूनी और मनगढ़ंत आरोप को उठाने के पीछे मुख्य कारण यह है कि 2.05.2007 को ईआई आईसी होशियार सिंह पहले से ही छुट्टी पर थे और शिकायतकर्ता और कांस्टेबल मंजीत कुमार नंबर J626/KNL अपीलकर्ता के साथ एयर स्ट्रिप पर मौजूद थे। पुलिस पोस्ट कलवेहड़ी, कांस्टेबल मंजीत कुमार ने अपीलकर्ता से अनुरोध किया कि उसे अपने उद्देश्य के लिए कुछ दवा के लिए डॉक्टर के पास जाने की अनुमति दी जाए। 'अपीलकर्ता ने उसे इस शर्त पर अनुमति दी कि वह 22.05.2007 को सुबह जल्दी वापस आ जाएगा। इस बीच, शिकायतकर्ता ने इस दलील पर आपत्ति जताई कि वह अपने परिवार के सदस्यों को देखने के लिए अपने मूल स्थान पर जाएगा। अपीलकर्ता ने उससे कहा कि कांस्टेबल मंजीत कुमार के आने के तुरंत बाद उसे अपने मूल स्थान के लिए जाने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन शिकायतकर्ता व्यथित थी और एयर स्ट्रिप पर अपीलकर्ता के साथ अकेले होने का फायदा उठाते हुए, कलवेहरी अपीलकर्ता पर उसके साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का आरोप लगाने में कामयाब रही। "

(5) 'पुलिस महानिदेशक, हरियाणा ने 20.08.2008 को पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक को सज़ा आदेश में हस्तक्षेप करने वाली कोई कम करने वाली परिस्थितियाँ नहीं मिलीं।

(6) बर्खास्तगी का आदेश और अपील और पुनरीक्षण में पारित आदेश, जिनमें से अंतिम आदेश 20.08.2008 को पारित किया गया था, अंतिम हो गया क्योंकि याचिकाकर्ता ने किसी भी अदालत के समक्ष उन आदेशों पर सवाल नहीं उठाया था। याचिकाकर्ता ने जानबूझकर अपने पक्ष में आपराधिक मुकदमे के समापन की प्रतीक्षा की। 'अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, करनाल ने अपने फैसले और आदेश दिनांक 20.12.2012 द्वारा याचिकाकर्ता को यह कहते हुए बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष के साक्ष्य आरोपी को अपराध के लिए दोषी ठहराने या उचित संदेह से परे आरोप स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं थे, ट्रायल कोर्ट ने याचिकाकर्ता को बरी कर दिया उसे संदेह का लाभ देकर। यह ध्यान देने योग्य है कि शिकायतकर्ता कांस्टेबल अशोक कुमार ने मुकदमे में याचिकाकर्ता के खिलाफ गवाही दी और गवाह बॉक्स में अपने संस्करण का समर्थन किया।

(7) बरी होने पर, याचिकाकर्ता ने हंगामा किया और 31.01.2013 को ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित बरी के फैसले के आलोक में बहाली की प्रार्थना करते हुए एक अभ्यावेदन दिया। बताया जा रहा है कि इस प्रतिनिधित्व पर अब तक फैसला नहीं हुआ है. यह सब याचिकाकर्ता को 20.08.2008 को संशोधन में बरकरार रखे गए बर्खास्तगी आदेश को रद्द करने की प्रार्थना करने के लिए इस न्यायालय में लाया गया है।

(8) विचार के लिए जो संक्षिप्त प्रश्न उठता है वह यह है कि क्या पुलिस महानिदेशक द्वारा पुनरीक्षण तक बर्खास्तगी आदेश की पुष्टि की गई है। विभागीय कार्यवाही से उत्पन्न होने वाले मामले को बाद में दोषमुक्ति के कारण वापस लिया जा सकता है, बदला जा सकता है, संशोधित किया जा सकता है या रद्द किया जा सकता है।

(9) याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री मनोज ताया को यह जांच करते हुए सुना कि क्या कारण स्वीकार करने योग्य है।

(10) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का कहना है कि आरोपों के एक ही सेट पर आपराधिक मामले में बरी होने के परिणामस्वरूप, विभागीय कार्यवाही के बाद पारित बर्खास्तगी आदेश का आधार हटा दिया गया है और रास्ते में सभी पूर्व-मौजूदा बाधाएं दूर हो गई हैं। याचिकाकर्ता को रोक दिया गया है और अब सफलता की राह में कोई बाधा या दुर्गम बाधा नहीं है। 20.12.2012 को ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए बरी के निष्कर्ष, हालांकि संदेह का लाभ देते हुए, याचिकाकर्ता के पक्ष में भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उपाय चुनकर इस न्यायालय से संपर्क करने के लिए कार्रवाई का कारण बनाते हैं, जिसका उसे अधिकार है। . यह आग्रह किया जाता है कि केवल इसलिए कि विभागीय कार्यवाही मुकदमे से काफी पहले समाप्त हो गई है और शिकायतकर्ता और गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं, शिकायतकर्ता कांस्टेबल अशोक कुमार के बयान पर पूरी तरह भरोसा न करते हुए ट्रायल कोर्ट द्वारा आए निष्कर्षों को खारिज करने का पर्याप्त कारण नहीं है।

(11) लेकिन इस तर्क में, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील विभागीय कार्यवाही और आपराधिक मुकदमे में आरोप लाने के लिए आवश्यक सबूत के मानक के बीच अच्छी तरह से स्थापित अंतर को भूल जाते हैं। यह दोहराना सामान्य बात है कि एक संभावनाओं की प्रबलता पर आधारित है जबकि दूसरा किसी भी उचित संदेह की छाया से परे प्रमाण पर आधारित है। यद्यपि आपराधिक कानून में संदेह का लाभ देकर आपराधिक आरोप से बरी करना बाकी दुनिया के लिए निर्दोषता के बराबर है, लेकिन सेवा न्यायशास्त्र में सेवा में बने रहने के लिए सिद्धांत को आँख बंद करके स्वीकार या पालन नहीं किया जा सकता है। एक एकीकृत बल में सेवा के लिए आवश्यक उच्च नैतिक और नैतिक मानकों से निपटने और केवल बेदाग सर्वश्रेष्ठ को पुलिस बलों में प्रवेश देने में शुद्धता और पूर्ण सत्यता बनाए रखने के साथ-साथ अब यह वर्तमान आवश्यकता है कि आवेदन पत्रों में दिए गए बयानों में सच्चे और ईमानदार खुलासे हों। विज्ञापित सरकारी पदों पर नियुक्तियों की मांग करते समय एफआईआर/एस के पंजीकरण के पिछले आपराधिक रिकॉर्ड और उसके बाद जांच और परीक्षण के चरणों और उनके इकबालिया आवेदनों का खुलासा करना और गैर-नियुक्ति को उचित ठहराने वाले भौतिक तथ्यों के गैर-प्रकटीकरण के प्रभाव के संबंध में, मुद्दा सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के उच्चतम नैतिक मानकों की मांग करने वाले, विशेष रूप से उन लोगों से, जो वेतन पर लगे हुए हैं, इसमें शामिल सार्वजनिक हित के खिलाफ संदिग्ध लोगों को सार्वजनिक कार्यालय में प्रवेश देने की प्रवृत्ति से उत्पन्न होने वाले बड़े सामाजिक मुद्दों के कैनवास पर जांच की जानी चाहिए। नागरिकों के सेवा जीवन के हर दिन जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सार्वजनिक निधि से भुगतान किया जाता है, 'यह दो अल्पविरामों के बीच लगाने के लिए एक बड़ा वाक्य हो सकता है लेकिन आधुनिक शासन-शुद्धि का व्याकरण अब शुरू होना चाहिए क्योंकि इससे पहले कभी भी विश्वास का पूर्ण नुकसान नहीं हुआ है कार्यालयधारकों में और विश्वास की हानि से होने वाली अतिरिक्त हानि जो आम तौर पर दागी भर्ती प्रक्रियाओं के साथ चलती है, उन प्रतिष्ठित व्यक्तियों की मूल सोच को बहाल किया जाना चाहिए जिन्होंने संविधान सभा के थिंक टैंक का गठन किया जिसने हमें हमारा संविधान और लोक सेवा आयोग दिया। उन्हें अपनी संवैधानिक स्थिति बचाने की जरूरत है। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि न्यायालय विश्वास, विश्वास और आपसी सम्मान को बढ़ावा देने के लिए अनुस्मारक कहे, जब शासन अदूरदर्शी, निचले स्तर पर और कंचनजंगा से भी अधिक भ्रष्टाचार वाला प्रतीत होता है। 'सत्तारूढ़ सिद्धांत यह है कि पुलिस विभाग में सुधार की बहुत आवश्यकता है, जिसे लोगों की आकांक्षाओं और आशाओं के अनुरूप शुरू किया जाना चाहिए। इसका हम पर और हमारी सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ता है और जो लोग हमारे हवाई अड्डों और हमारे जीवन की रक्षा करते हैं, उन्हें सीज़र की पत्नी की तरह संदेह से ऊपर होना चाहिए।

(12) विषयांतर के बावजूद, 20.08.2008 को पुलिस महानिदेशक, हरियाणा द्वारा पुनरीक्षण याचिका को खारिज करने के साथ याचिकाकर्ता के पक्ष में कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ। यदि 20.08.2008 को पुनरीक्षण याचिका की अस्वीकृति के चरण तक बर्खास्तगी के आक्षेपित आदेशों पर सवाल उठाने के लिए एक नागरिक मुकदमा लाया गया था, तो इसे 20.08.2011 या अधिकतम 20.10.2008 (एसआईसी) को समय-अवरुद्ध कर दिया गया होगा। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 80 के तहत दो महीने के नोटिस की अनुमति। मुकदमे को कार्रवाई के कारण के खिलाफ रोक दिया जाएगा, फिर आम तौर पर एक रिट तब तक झूठ नहीं होगी जब तक कि यह न्यायालय अपने असाधारण रिट क्षेत्राधिकार में मौलिक उल्लंघनों या उल्लंघनों में गंभीर न पाए। अधिकारों या मानवाधिकारों का उल्लंघन शामिल है जिसके लिए तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है। तब शायद यह न्यायालय सीमा अधिनियम, 1963 या विशेष वैधानिक कानून द्वारा निर्धारित ऐसी अन्य बाधाओं के तहत कार्रवाई करने के लिए निर्धारित अवधि से बाहर होने के परिणामस्वरूप होने वाली देरी, विलंब और बाधा के सिद्धांतों पर उचित दावे को खारिज करने पर जोर नहीं दे सकता है।

(13) यह कहा जा सकता है कि भले ही याचिकाकर्ता के पास बर्खास्तगी आदेश को चुनौती देने का अधिकार है, लेकिन सीमा की रोक के संचालन से उपचार छीन लिया जाता है, जो कार्रवाई के कारण की प्राप्ति की तारीख से तीन साल है। वर्तमान में विचार करने वाली बात यह है कि क्या दोषमुक्ति के निर्णय को कार्रवाई के अधिकार या कार्रवाई के कारण को जन्म देने वाला कहा जा सकता है। मुझे नहीं लगता कि इस न्यायालय के लिए यह मानना सही होगा कि किसी घटना के आधार पर आपराधिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा बरी करने का निर्णय, जो पहले विभागीय कार्यवाही में हुआ हो और जुर्माना लगाया गया हो, उसके खिलाफ कार्रवाई का एक नया कारण पैदा करेगा। एक प्रतिकूल प्रशासनिक आदेश अंतिम रूप ले चुका है या कानून की अदालत में दंड के खिलाफ लागू किया जा सकता है, उदाहरण के लिए, सेवा से बर्खास्तगी, सबूत के मानक दोनों के अलग होने के बावजूद।

(14) अंत में यह आग्रह किया गया कि याचिकाकर्ता ने घटना से 32 साल पहले फॉर्मोर्क में सेवा की थी, 1975 में कांस्टेबल के रूप में उसकी भर्ती का वर्ष दिया गया था और उसे बर्खास्तगी की कठोरतम सजा न देने का पर्याप्त औचित्य होना चाहिए, जो तर्क

प्रभावित नहीं करता है या मुझे हिरासत में लो. 29.11.2007 के आदेश में अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने विशेष रूप से माना था कि डिफॉल्टर का कदाचार निश्चित रूप से सबसे गंभीर प्रकार का है और उसकी सेवा की अवधि आदि को देखते हुए उसके साथ व्यवहार करने में कोई उदारता नहीं दिखाई जा सकती है क्योंकि यह एक भावनात्मक निर्णय होगा। पुलिस बल के हित के विरुद्ध। कदाचार के गंभीरतम कृत्यों से जुड़े पीपीआर, 1934 के तहत मामलों से निपटने के दौरान यह पूरी तरह से अच्छा और स्वीकार्य कारण है। क्या गंभीर और गंभीर है यह डिग्रियों का प्रश्न है जिसमें कई परिवर्तनशील कारक शामिल होते हैं जिनका सबसे अच्छा निर्णय वे लोग करते हैं जिन्हें पुलिस बल चलाना है। याचिकाकर्ता के पास न तो योग्यता के आधार पर, न ही समानता के आधार पर और न ही किसी सहानुभूतिपूर्ण विचार के आधार पर मामला है। दिए गए तथ्य स्थितियों के एक सेट के खिलाफ परीक्षण की गई सहानुभूति और करुणा पूरी तरह से व्यक्तिपरक राय होती है जो आमतौर पर न्यायिक रूप से प्रबंधनीय मानकों से परे होती है और इससे भी बुरी बात यह है कि वे सरकारी कार्यालय में निर्णय-निर्माता-सह-कर्तव्य-धारक से और अदालत से अदालत तक भिन्न हो सकते हैं।

(15) संपूर्ण परिस्थितियों में यह नहीं कहा जा सकता कि याचिकाकर्ता किसी भी बर्खास्तगी से कम का हकदार था, मुझे नहीं लगता। प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष याचिकाकर्ता द्वारा किया गया बचाव न केवल गंदा, बेईमान है, बल्कि एक पुलिस अधिकारी द्वारा खुद को दोषमुक्त करने के लिए उचित और गलत तरीकों का उपयोग करना भी निंदनीय है। यह उनके चरित्र का दुखद प्रतिबिंब है कि वह इतने नीचे गिर गए कि उन्होंने अपने बयान का समर्थन करने के लिए बचाव गवाह के रूप में अपने सहयोगियों को यह दिखाने के लिए उकसाया कि शिकायतकर्ता कांस्टेबल अशोक कुमार एक ऐसा व्यक्ति था जिसे अप्राकृतिक यौनाचार के लिए दिया गया था और वह उनमें से एक को गवाही से हटाने की हद तक चले गए। कि उसने उसे एक रिक्शेवाले के साथ देखा था. मैं कहता हूं कि अगर यह मान भी लिया जाए कि वह अप्राकृतिक इच्छाओं का शिकार था, तो भी यह याचिकाकर्ता को उस पर हमला करने या पुलिस बल से गवाहों को बुलाकर हताशा में इस घटिया तरीके से गंदगी फैलाने के लिए उचित नहीं ठहराएगा। यह तथ्य कि याचिकाकर्ता बर्खास्तगी के आदेश के खिलाफ कानूनी सहारा लिए बिना चार साल तक बैठा रहा, अपने आप में बहुत कुछ कहता है और खराब अंतरात्मा को उजागर करता है। कोर्ट को उन लोगों को नहीं जगाना चाहिए जो लंबी नींद सो चुके हैं।'

(16) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने इस न्यायालय से संपर्क करने में देरी को उचित ठहराने की मांग करते हुए आग्रह किया कि याचिकाकर्ता को आसानी से दोषी ठहराया गया था, इस रिट याचिका को दायर करने का कोई अवसर नहीं था और इसलिए, उसके पास अंतिम का इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ट्रायल कोर्ट का परिणाम. मुझे डर है कि यह पर्याप्त स्पष्टीकरण नहीं है या गलत कारणों से इस न्यायालय में आने में हुई अत्यधिक देरी को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त कारण नहीं है।

(17) बर्खास्तगी आदेशों के खिलाफ हस्तक्षेप की कोई उचित गारंटी नहीं दी गई है, जो बहुत पहले ही अंतिम रूप ले चुके हैं। 'उन्हें कानूनी और वैध माना जाता है और वे किसी भी दुर्बलता से पीड़ित नहीं हैं।

(18) कोई योग्यता नहीं। नियमित सुनवाई के लिए प्रवेश के योग्य नहीं होने के कारण इसे खारिज कर दिया गया।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

सृष्टि
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
कुरूक्षेत्र, हरियाणा